I. राउरकेला इस्पात संयंत्र आधुनिकीकरण :

1. कच्चा माल रख-रखाव प्रणाली चरण-II — मूल्य 92.72 करोड़ रु०

	अब तक किया गया वास्तविक कार्य
मूल इंजीनियरी	100%
सिविल कार्य	50%
प्राप्त किया गया इस्पात (7500 टन में से)	3400 टन
क्रयादेश	98%
एच०ई०सी० द्वारा आपूर्ति (1000 टन में से)	600 टन

2. अनवरत ढलाई संयंत्र — मूल्य 174.92 करोड़ रु०
(इसके कार्यक्षेत्र में सिविल और संरचनात्मक कार्य शामिल नहीं है)

		क्रियाकलाप	अब तक किया गया वास्तविक कार्य
(क) एच०ई०सी० को क्रयादेश	92.17 करोड़	मूल इंजीनियरी	98.2%
(ख) एम०एम०एस०, जर्मनी को राउरकेला इस्पात संयंत्र से सीधे क्रयादेश	57.79 करोड़		
(ग) शुल्क	24.97 करोड़	विस्तृत इंजीनियरी	54%
योग	174.92 करोड़		

किए गए अनुबंध के अनुसार उपकरण की आपूर्ति जनवरी, 1994 से आरंभ होगी।

II. दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का आधुनिकरण :

1. चक्र और अक्ष संयंत्र, दुर्गापुर का (टनेज की आधार पर आधुनिकरण)	41.23 करोड़	100% पूरा किया गया
2. उपकरण आपूर्ति		
(क) लेडल क्रेनें	28.74 करोड़	99.3% पूरा किया गया
(ख) हैमर क्रेशर	2.77 करोड़	100% पूरा किया गया
(ग) 16 घन मी० स्लैग कप्स	2.26 करोड़	99.3% पूरा किया गया
(घ) 143 टी होट मेटल लेडल्स	1.20 करोड़	98.4% पूरा किया गया
(ङ) ग्रिज्ली हिम्मे पुर्जे	0.65 करोड़	100% पूरा किया गया
योग	76.85 करोड़	

Problems in Restructuring PSUs

987. SHRI RAMDAS AGARWAL : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to a news item published in the Financial Express dated the 20th November, 1993 under the caption "Inter-Ministerial wrangles hit PSU restructuring plan" stating that the Ministries involved are pulling in different directions over the implementation of the Onkar Goswami report on industrial sickness and corporate restructuring ;

(b) if so, the details thereof, and what are the specific weas of action for stimulating the revival of PSUs envisage/advocated by the Ooswami Committee ; and

(fc) what steps Government propose to take to denationalise the PSUs, also indicating the progress so far made for recovery of corporate debt to secured creditors ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY) (SHRIMATI KRISHNA SAHI) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.